from 1-6-1974 after taking into consideration the recommendations of the Third Pay Commission and also the increase in the price of petrol upto that date.

(b) The rates of mileage allowances have not been revised after 1-6-1974, as there has been no appreciable increase in the price of petrol after that date.

Finalisation of Missing Credits in AGCW&M and AGCR

1705. SHRI S. D. SOMASUNDARAM: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether in spite of long time elapsed after the departmentalisation of accounts lot of missing credits in G.P.F. of Central Government employees have not been finalised by the A.G.C.W. & M and A.G.C.R. etc. before the transfer of G.P.F. accounts to the concerned department; and

(b) if so, the reasons for not fixing the target date for reconciliation of missing credits in G.P.F. and bringing all accounts uptodate?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). The Comptroller & Auditor General issued instructions on 10-9-1976 to all the Accountants General to complete the Provident Fund Accounts of all subscribers for the year 1975-76 and issue Annual Accounts Statements latest by 31-10-1976; and also to make all-out efforts to locate and settle the differences to the maximum extent posible before balances are transferred to the Departmental Pay & Accounts Offices. However, due to the large numbers of missing credits and complexity of the cases, accounts are being transferred with missing credits. The computer-based accounts which were maintained by the A.G.C.R. were taken over on 1-10-1976 by the Ministry of Finance, on an "as is where is" basis and action is being taken to clear the arrears of postings and to trace missing credits.

वर्ष 1976–77 के दौरान दिये गये आयात लाइसेंस

1706. **श्री मीठा लाल पटेल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 में किन-किन वस्तुओं के लिये आयात लाइसेंस दिये गये थे, जबकि वे वस्तुएं देश में उपलब्ध थीं और ये लाइसेंस कितने मूल्य के थे तथा किन-किन के लिये इन वस्तुओं का आयात किया गया था;

(ख) क्या वे वस्तुयें ऊंचे मूल्य पर उपलब्ध थीं अथवा वे घटिया किस्म की थीं अथवा वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थीं; और

(ग) क्या वर्ष 1977–78 में इन वस्तुओं का दोबारा आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) ऐसी जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है । इस जानकारी को एकत्र करने के लिये आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के मुख्यालय और विभिन्न पत्तन कार्यालयों द्वारा जारी किये गये सैकड़ों लाइसेंसों की जांच करनी होगी । परन्तु यह जानकारी साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित की जाती है । जिनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं ।

(ख) प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी आयातों की सिफारिश करते समय स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी, कीमत, सुपुर्दगी-अवधि आदि पर समुचित ध्यान देते हैं और आयात नीति के उपबन्धों के अध्यधीन कार्य करते हैं ।